'डिजिटल इंडिया' करेगा गांवों का कायाकल्प

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

यूं तो डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी परियोजनाओं का दायरा राष्ट्रव्यापी है किंतु ग्रामीण भारत के संदर्भ में देखें तो इन योजनाओं में हमारे गांव-देहात का डिजिटल कायाकल्प करने की संभावनाएं निहित हैं। यह योजना एक व्यापक डिजिटल आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ-साथ पंचायती राज को मजबूत, प्रभावी तथा जवाबदेह बनाने में योगदान दे सकती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह पंचायती राज का डिजिटलीकरण करने में भी योगदान देंगी और गांवों को ज्ञान अर्थव्यवस्था की लघु इकाई बनने के लिए प्रेरित करेंगी। सबसे अहम कामयाबी डिजिटल इंडिया से यह होगी कि यह हमारे गांवों और तकनीक के बीच की मौजूदा दूरी को पाटने में योगदान देंगी।

यूं तो डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी परियोजनाओं का दायरा राष्ट्रव्यापी है किंतु ग्रामीण भारत के संदर्भ में देखें तो इन योजनाओं में हमारे गांव–देहात का डिजिटल कायाकल्प करने की संभावनाएं निहित हैं। यह योजना एक व्यापक डिजिटल आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ–साथ पंचायती राज को मजबूत, प्रभावी तथा जवाबदेह बनाने में योगदान दे सकती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह पंचायती राज का डिजिटलीकरण करने में भी योगदान देंगी और गांवों को ज्ञान अर्थव्यवस्था की लघु इकाई बनने के लिए प्रेरित करेगी। सबसे अहम कामयाबी डिजिटल इंडिया से यह होगी कि यह हमारे गाँवों और तकनीक के बीच की मौजूदा दूरी को पाटने में योगदान देगी।

हालांकि डिजिटल इंडिया के तहत ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा से जोड़ने की घोषणा ने सबका ध्यान खींचा है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना का अकेला प्रावधान नहीं है जो गांवों में परिवर्तन के दौर का सूत्रपात कर सकता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्थापना मात्र ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस तंत्र के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाई जाने वाली सेवाएं। इनमें सबसे प्रमुख है ई–प्रशासन जो केंद्र तथा राज्य सरकारों की सेवाओं को गांव–गांव तक फैले उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि आज भी कई राज्यों में छोटे स्तर पर ई–प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं और केंद्र व राज्य सरकारों की अनेक सेवाएं वेबसाइटों के माध्यम से आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ये सुविधाएं शहरी लोगों तक ही पहुंचकर रह जाती हैं। गांवों में इंटरनेट की भरोसेमंद सुविधा का मौजूद न होना, कंप्यूटरों

20,000 पंचायतों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क का काम पूरा

हाईस्पीड ब्रॉडबैंक कनेक्टिविटी देने के लिए मार्च 2015 तक 20,000 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) का काम किया जा चुका है। अन्य 10,000 ग्राम पंचायतों में यह कार्य लगभग पूरा होने के कगार पर है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2015 तक 50,000 ग्राम पंचायतों में यह नेटवर्क शुरू करने का लक्ष्य रखा था। यह परियोजना 2011 में बनाई गई थी और सभी पंचायतों को 2013 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य तय किया गया था। बाद में, उसे आगे बढ़ाकर सितंबर, 2015 कर दिया गया था। लेकिन, नई सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और 50,000 ग्राम पंचायतों को मार्च, 2016 तक और शेष ग्राम पंचायतों को 2016 के अंत तक यह कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य तय किया गया है।

देश की 10 ग्राम पंचायतों का होगा पूर्ण डिजिटलीकरण

गांवों को विकास के मॉडल के रूप में तब्दील करने के उद्देश्य से उन्हें गोद लेने के बाद केन्द्र सरकार अब पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए गोद लेना चाहती है। उसने देश के 10 राज्यों की 10 पंचायतों को चुना है जो नियोजन, एकाउंटिंग और प्रमाणपत्र, लाइसेंस आदि जारी करने जैसी सेवाएं ऑनलाइन देंगी। देश में 10 ग्राम पंचायतों को दिसम्बर, 2015 तक ई–पंचायत के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है, जो मॉडल्स के बतौर कार्य करेंगे। राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे इन पंचायतों को मॉडल्स के रूप में विकसित करने के लिए समन्वित प्रयास करें।

का अभाव और ऊपर से बिजली संकट नागरिकों को ई–सुविधाओं से वंचित कर देता है। डिजिटल इंडिया के नौ बुनियादी लक्ष्यों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना को अत्यधिक अहमियत दी जा रही है जिससे इस समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद बंधी है।

हर एक पंचायत के साथ अनेक गांव और ढाणियां जुड़े होते हैं। उस लिहाज से इन सेवाओं का दायरा और भी व्यापक हो जाएगा। केंद्र सरकार के दूरसंचार संस्थानों– भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के साथ–साथ रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम इस कार्य में हाथ बंटाने जा रही है। इस बीच, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने घोषणा की है कि वह अलग से पांच लाख भारतीय गाँवों में व्हाइट बैंड टेलीविजन ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने के लिए काम करने जा रही है। यह फाइबर ऑप्टिक से अलग, अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से लागू की जा सकने वाली आधुनिक तकनीक है जिसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका में सफलतापूर्वक किया है।

ई–प्रशासन तंत्र को प्राथमिकता दिए जाने का अर्थ है दोनों छोरों पर डिजिटल विकास। तहसील से लेकर जिला, राज्य और केंद्र की प्रशासनिक सेवाएं इंटरनेट के जरिए आम ग्रामीणों तक पहुंचने का अप्रत्यक्ष अर्थ है गांव के स्तर पर भी इन सुविधाओं को प्राप्त करने का तंत्र विकसित किया जाना। जाहिर है, इस तंत्र के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे तथा कुछ हद तक आधारभूत विकास भी होगा। सूचनाओं को भेजने तथा पाने के लिए कंप्यूटर पर काम करने में कुशल युवकों की नियुक्तियां होंगी। आसपास प्रिंट लेने, फोटोकॉपी करने आदि की सुविधाएं आ जाएंगी। जहां लोग जुटेंगे वहां छोटे–मोटे अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे जैसे चाय की दुकानें। गांवों में तकनीकी संस्कृति पर चर्चा शुरू होगी तो कंप्यूटरों व तकनीकी प्रशिक्षण के प्रति जिज्ञासा भी उपजेगी। जब भरोसेमंद इंटरनेट और दूसरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो फिर गैर–सरकारी कारोबारी संस्थान भी गांवों तक पहुंच सकेंगे। क्राइसिल के एक अध्ययन के अनुसार इस समय भारत में ई–वाणिज्य माध्यमों के जरिए होने वाली बिक्री का सिर्फ एक फीसदी हिस्सा गांवों से आता है। इंटरनेट की मौजूदगी इस प्रतिशत को तो बढ़ाएगी ही, वह बड़ी कंपनियों को गांवों तक डिलीवरी के माध्यम स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करेगी। इतना ही नहीं, गांवों में उत्पादित फसलों, फलों–सब्जियों, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण उत्पादों के लिए नए बाजार भी खुलेंगे। कुल मिलाकर ग्राम पंचायतों तथा गांवों के समग्र वातावरण में तकनीक का सकारात्मक हस्तक्षेप होने जा रहा है जो डिजिटलीकरण के साथ–साथ कुछ हद तक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।

गांवों में रोजगार के मौके और भी बनेंगे। जिन कंपनियों ने डिजिटल इंडिया के तहत पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का वायदा किया है उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उनकी परियोजनाओं से करीब 18 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसका एक हिस्सा ग्रामीण युवकों के हिस्से में भी जाएगा। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी बड़ा व्यापक सिद्ध होने वाला है। उसकी देखरेख का कार्य भी चुनौतीपूर्ण होगा। इस कार्य के लिए गांवों के स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। सन् 2018 तक 42,000 गांवों में निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है। एक विशाल और नए तंत्र की

स्थापना में रोजगार सृजन की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं।

गांवों के लिहाज से डिजिटल इंडिया का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है–आउटसोर्सिंग उद्योग में गांवों की भूमिका सुनिश्चित करना। घरेलू कंपनियों की कॉल सेंटर आधारित जरूरतों को पूरा करने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक तो वहां पर दफ्तर स्थापित करना आसान और सस्ता है तथा दूसरी ओर मानव संसाधन भी शहरों की अपेक्षा सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकते हैं। परिवहन, निर्माण कार्य आदि के खर्च भी कम हैं। इन्हें देखते हुए कुछ राज्यों में ग्रामीण बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) के प्रयोग हुए हैं लेकिन आज भी ये बहुत छोटे स्तर पर हैं। ऐसे प्रयोगों के मार्ग में आने वाली दो बड़ी अड़चनें हैं–निर्बाध बिजली की अनुपलब्धता और भरोसेमंद दूरसंचार व इंटरनेट सेवाओं का मौजूद न होना। एक अन्य अहम समस्या है भली प्रकार प्रशिक्षित युवक–युवतियों का उपलब्ध न होना। केंद्र सरकार ने इन सभी व्यावहारिक पहलुओं को समझा है और इनके समाधान के लिए कार्यवाही की जा रही है।

प्रशिक्षित युवक–युवतियों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हाथ में लिया है। छोटे गांवों, कस्बों और शहरों के एक करोड़ छात्रों को पांच साल के भीतर प्रशिक्षित करने की योजना है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। कई दूरसंचार कंपनियां भी छात्रों को कौशल से लैस करने के लिए आगे आई हैं। वे अपने स्तर पर छोटे कस्बों में पांच लाख लोगों को प्रशिक्षित करने जा रही हैं।

कॉमन सर्विस सेंटरों का होगा ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक विस्तार

केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों का ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक विस्तार करेगी। अब तक ये कॉमन सर्विस सेंटर डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं। दूरसंचार एवं आई.टी. मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 10 मार्च को हुई पहली ऑल वूमेन विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर कांफ्रेंस में कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन केंद्रों के जरिए महिला सशक्तीकरण की आशा है। डिटिजल इंडिया प्रोग्राम के तहत इनकी संख्या 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 की जाएगी। सरकार ने डिटिजल इंडिया प्रोग्राम के तहत 4,750 करोड़ रु. की लागत से 2017 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है। कॉमन सर्विस सेंटरों के विस्तार की योजना अंतिम चरण में है और इसकी शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। कुछ राज्यों में एक रुपये मासिक किराए पर पंचायत कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए ताकि अधिकाधिक लोग इन केंद्रों की सेवाओं का लाभ उठाएं। देश भर में कॉमन सर्विस सेंटरों का परिचालन करने वाली महिला उद्यमियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। बिहार के एक गांव की महिला उद्यमी वैजयंती ने कहा कि यद्यपि वह कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थीं, फिर भी कॉमन सर्विस सेंटर अपनाया और अब कंप्यूटर चला लेती हैं तथा अपने गांव में सेवाएं दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की एक महिला उद्यमी तनुजा ने बताया कि हम जन–धन योजना के तहत जनता को बैंक खाते खोलने में मदद कर रहे हैं। मुझे कंप्यूटर को छूने में डर लगता था और सोचती थी कि यदि कोई गलत बटन दब गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब यह डर दूर हो गया है एवं दिलचस्पी के साथ कंप्यूटर पर काम करती हूं। आधार कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं पाने के लिए लोग सेंटर पर आते हैं।

अगर इतने बड़े स्तर (1.05 करोड़) पर हमारे युवा तकनीकी माध्यमों में कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो उससे गांवों में होने वाले समग्र आर्थिक–सामाजिक बदलाव का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत संभव है कि अगला दशक भारत के गांवों के लिए समृद्धि के मार्ग पर मजबूत कदम बढ़ाने का दशक सिद्ध हो।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विषय के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : balendndhadhich@gmail.com